

मनरेगा भुगतान में वलंब

प्रलिस के लयः

[आधार भुगतान बरजि ससलडम \(APBS\)](#), [महातमा गांधी राषुड्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनलडड \(MGNREGA\) डोजना](#), राषुड्रीय इलेकुडरॉनकल नधल अंतरण डरणाली (NEFMS),

डेनुस के लयः

डनरेगा डोजना के तहत वलंबतल डुगतान का डुदुदु, डनरेगा डोजना से संबंघतल कुनौतलडल, आगे की राह और डनरेगा डोजना को डजडूत करने के सडडडडन ।

[सुरोतः डडउन डू अरथ](#)

करुा डें करुुडु?

१११११११ ११११११ ११ १११११ १११११११११११११११ (११११११११११) डें डुरकाशतल एक हालडल अधुडडन से डता कुला है कलकुंडर सरकार डुर [महातमा गांधी राषुड्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनलडड \(MGNREGA\) डोजना](#) के शुरडकलुु को वलंबतल डजडूरी के रूड डें 39 करोड रूडुड डकाडल है ।

- अधुडडन डें वरुष 2021-22 डें 31.36 डललडडन वेतन लेनडेन का वशल्लेषण कडल डया और डडल डया कल आधार-आधारतल डुगतान डरणाली (ABPS) तथल डडत-आधारतल वेतन वतलरुण ने डुगतान की गतल डें सुडर करने के डडडड देरी का कारण डनल है ।

डनरेगा डुगतान से संबंघतल डुरडुख नडलकरुष कडल है?

- ABPS की अकुशलताः डनवरी, 2024** डें ABPS की अनवलरुडतल के डड केवल 43% डनरेगा शुरडकलुु ही इसके लडल डडतुर थे ।
 - ABPS के कारण देशडर डें हुडू अधुषतल देरी की कुषतडूरतल राशल 400 करोड रूडुड तक हो सकतल है, जो डुगतान को सुवुडवसुथतल करने और डडरदरशतल डें सुडर लाने के सरकार के डडवे के वडलरलत है ।
- अडरुडडडत नधलः** डुगतान डें देरी का कारण डुखुड रूड से कुंडर सरकार डुवारा डडरल की गडू नधल कल अडरुडडडत होनल है ।
 - वतलत वरुष 2021-22 डें केवल 29% डुगतान ही अनवलरुड 7-दवलसीड अवधल के अंडर संसलधतल कडल डुग ।
- डडट आडवंटन डें कडलः** अधुडडन डें डनरेगा के लडल वतलतडुषण की कडल डुर डुरकाश डडलल डया है, डसलडें वतलत वरुष 2021-22 डें डडट आडवंटन सकल घरेलू उतुडडड (GDP) का केवल 0.41% (जुु ग्रामीण रोज़गार की डडंग को डुरल करने के लडल आडवशुडक सुतर से काडल कडल है) थल ।
 - कुुवडल-डहलडडरल (वरुष 2020-21) के डुरलरन डह केवल 0.56% थल, जो वतलत वरुष 2023-24 एवं वतलत वरुष 2024-25 डें घटकर 0.2% रह डया ।
 - शुुधकरुतुतलओुु का सुडुडलव है कल डूरुण करुड डडंग को डुरल करने के लडल इसका डडट कडल से कडल 4 गुनल (अरुथलत सकल घरेलू उतुडडड का लडडड 1.2% से 1.5%) अधकल होनल डलहडल ।
- डडत-आधारतल डजडूरी डुगतान और असडडनतलरुुः** वरुष 2021 डें शुुरु कडल डुग डडत-आधारतल डजडूरी डुथककरण (डसलके तहत डुगतान कुु अनुसूकुतल डडतल, अनुसूकुतल डनडडतल एवं 'अनुड' शुरेणडलुु डें वरुगीकुत कडल डया) के डड डह देखल डया कल अनुसूकुतल डडतल, अनुसूकुतल डनडडतल के शुरडकलुु की तुलनल डें 'अनुड' डडतल के शुरडकलुु के लडल डुगतान डें देरी हुडू ।
 - 'अनुड' डडतल के केवल 33% डुगतान 7 डनलुु के अंडर संसलधतल कडल डुग, डडकल अनुसूकुतल डनडडतलुु के लडल डह आंकडुड 42% तथल अनुसूकुतल डडतलुु के लडल 47% थल ।

डनरेगा अधनलडड कडल है?

- डरकुडडः**
 - डह सलडलडकल सुरकुषल के लडल एक कुंडर डुरलडुडतल डोजना है डसलकल उदुदुशुड डरत डें ग्रामीण रोज़गार की गारंटी डुरडडन करनल है ।
 - इसे वरुष 2005 डें ग्रामीण वकलस डंतुरलडल के तहत अधनलडडतल कडल डया थल ।

- **उद्देश्य:** अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक पंजीकृत वयस्क ग्रामीण परिवारों को **कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार** उपलब्ध कराना।
- **कवरेज:** यह योजना **100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर** पूरे देश में लागू है।
- **मांग-आधारित ढाँचा:** मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है; यदि **15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है**, तो श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होते हैं, जो पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम पारिश्रमिक का एक-चौथाई और उसके बाद न्यूनतम पारिश्रमिक का आधा होता है।
- **वर्केंद्रीकृत योजना:** इस योजना में **आधारिक स्तर पर नथियोजन किये जाने पर ज़ोर दिया जाता है**, जिसमें कम से कम **50% कार्य** ग्रामसभा की सफाईकारियों के आधार पर **ग्राम पंचायतों** द्वारा नषिपादित किया जाता है।
- **नधि साझाकरण:** केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का **100%** और सामग्री लागत का **75%** वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें सामग्री लागत का **25%** योगदान देती हैं, जिससे कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है।
- **पारिश्रमिक भुगतान तंत्र:** योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक, **राज्य-वशिष्ट न्यूनतम पारिश्रमिक दरों पर आधारित होती है** और पारदर्शिता के लिये प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के बैंक या आधार-लकिड खातों में इसका भुगतान किया जाता है।
 - वलिंबति भुगतान के लिये प्रतदिनि अवैतनकि पारिश्रमिक की **0.05% प्रतपूरतप्रदान की जाती जाता है**, जो उपस्थितिनामावली (**Muster Roll**) का समापन किये जाने के **16वें दिन से शुरू होता है**।
- **दुर्घटना प्रतपूरत:** कार्यस्थल पर घायल हुए श्रमिक प्रतपूरतके पात्र होते हैं तथा मृत्यु अथवा स्थायी दवियांगता की स्थितिमें परिवारों को **अनुग्रह (Ex-Gratia) राशा** प्रदान की जाती है।
 - MGNREGA लाभार्थियों में **एक तहिई महिलाओं का होना आवश्यक है**, जिससे पारिश्रमिक और कार्य के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

//

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)

Employment Guarantee

Provides 100 days of wage employment per household

Work Assurance

Guarantees minimum wages, work within 15 days (else unemployment allowance)

Local Governance Implementation

Implemented through local governance structures like Gram Panchayats

Empowerment of Marginalized Communities

Focuses on empowering marginalized groups, especially women

Poverty Reduction

Aims to reduce poverty through job creation

Rural Economic Resilience

Contributes to rural economic resilience and sustainable development

MGNREGA पर प्रमुख नवीनतम आँकड़े

- **बजट 2024-25:**
 - **मनरेगा आवंटन:** मनरेगा बजट वित्त वर्ष 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपए था जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर **86,000 करोड़ रुपए** हो गया है।
 - **पारिश्रमिक दर में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूनतम औसत पारिश्रमिक दर में **7% की वृद्धि हुई**।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24:**
 - **महिला भागीदारी:** मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2019-20 में 54.8% थी जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर **58.9%** हो गई।
 - **जयोिटेगि और पारदर्शिता:** मनरेगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से परसिपत्तियों की **जयोिटेगि के साथ 99.9% भुगतान सटीकता** सुनिश्चित करता है।

मनरेगा योजना को प्रभावी बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

- पर्याप्त बजट आवंटन: सरकार को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, ग्रामीण रोजगार की बढ़ती मांग को पूरा करने और श्रमिकों की गरमा और आजीविका की रक्षा करने के लिये मनरेगा के बजट आवंटन में वृद्धि करनी चाहिये।
- डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार: सरकार को ABPS जैसी डिजिटल प्रणालियों की समीक्षा और सुधार करना चाहिये, तकनीकी बाधाओं को दूर करना चाहिये, बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना चाहिये और विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों के लिये पहुँच और उपयोगकर्त्ता-मतिरता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- जवाबदेही तंत्र को मज़बूत करना: सरकार को देरी के लिये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये, मनरेगा प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिये, और समय पर मजदूरी वितरण सुनिश्चित करने के लिये रपिपोर्टिंग, नगिरानी और शकियत नविरण प्रणालियों में सुधार करना चाहिये।
- भावी सुधार: भावी सुधारों में कुशल, पारदर्शी और न्यायसंगत वेतन वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जाति-आधारित असमानताओं से बचना चाहिये और सभी श्रमिकों के लिये उचित व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिये।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के उद्देश्यों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इसकी चुनौतियों का समाधान करने और इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वरित वरष प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के वयस्क सदस्य।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य।
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य।
- (D) कसिी भी घर के वयस्क सदस्य।

उत्तर: (D)